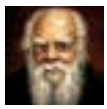

JYOTI BA PHULE SAHU JI MAHARAJ EVR. PERIYAR DR. AMBEDKAR NARAYAN GURU B.P. MANDAL V. P. SINGH

वाईस ऑफ ओबीसी

अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका
अंक 27 / मार्च-दिसम्बर 2024
सहयोग शुल्क : 50.00

अन्य पिछड़े वर्गों की

संसदीय समिति

का 20 जनवरी 2025 को चेन्नई दौरा

यूनियन बैंक ओबीसी कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण

अन्य पिछड़े वर्गों की संसदीय समिति

का 20 जनवरी 2025 को चेन्नई दौरा

संसदीय समिति की मीटिंग का विहंगम दृष्य

ऑल इंडिया यूनियन बैंक ओबीसी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ० अमृतांशु समिति के समक्ष अपनी बातें रखते हुए

ऑल इंडिया यूनियन बैंक ओबीसी कर्मचारी संघ की ओर से सम्मिलित समस्त पदाधिकारीगण

वॉइस ऑफ ओबीसी
अन्य पिछड़े वर्गों की समसामयिक पत्रिका
अंक 25 / मार्च 2022
सम्पूर्ण संचालन अवैतनिक
(सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन)
संरक्षक
प्रो0एस.एस. कुशवाहा
परामर्श
जी0 करूणानिधि
रवीन्द्र राम
प्रकाशक
रानी अमृतांशु
संपादक
अशोक आनंद
9415224153
मानद संपादक
डॉ0 अमृतांशु
9918306777
मानद उप संपादक
विनोद प्रसाद शर्मा
8765463674
विक्रांत कुमार
9918501891
प्रबंधक
अरविंद कुमार
सहयोग
शालीन कुमार
पत्राचार
ईमेल : aiobc.up@gmail.com
कटरा सं–77, पी0सी0एफ0प्लाजा
नदेसर, वाराणसी पिनः221002
सहयोग राशि : 100/-
Voice of OBC के खाते में दें
Name of Account : Voice of OBC,
SB A/C NO- 360502010165950,
IFSC CODE - UBINO536059,
Union Bank of India, Pandeypur Br., Varanasi
प्रकाशित रचनाओं से संपादन मंडल वैचारिक सहमति आवश्यक नही है।
प्रकाशित लेखों, संदर्भों के पुर्नप्रकाशन से पूर्व अनुमति लें।
समस्त वाद विवादों का निपटारा वाराणसी न्यायालय में मान्य
मुद्रक
प्रतीक प्रिंटर, नाटी इमली, वाराणसी

महत्वपूर्ण दौरा
● डॉ0 अमृतांशु

सत्यमेव जयते

ओबीसी संसदीय समिति

का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए चेन्नई में शैक्षणिक दौरा

दिनांक 20 जनवरी 2025 को तमिलनाडु चेन्नई में भारत सरकार की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संसदीय समिति का शैक्षणिक दौरा सम्पन्न हुआ। ज्ञात हो कि भारतीय संसदीय समिति 30 सांसदों की एक संवैधानिक समिति होती है जिसका गठन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वर्ष 2012 में हुई।

समिति के गठन को लेकर **AIOBC** महासंघ श्री जी0 करूणानिधि के नेतृत्व में वर्ष 2006 के बाद से ही काफी प्रयास किए। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न सांसदों से मिलकर संसदीय समिति की आवश्यकता को लेकर करूणानिधि एवं उनकी टीम ने यह जताने की कोशिश की कि अन्य पिछड़े वर्गों को लेकर जो प्रावधान भारत सरकार ने बनाए हैं उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक प्रभावशाली और मजबूत निगरानी इकाई का निर्माण किया जाए। अन्ततः यह सफलता वर्ष 2012 में प्राप्त हुई।

संसदीय समिति अन्य पिछड़े वर्गों के संवैधानिक प्रावधानों को लेकर भारत के विभिन्न प्रतिष्ठानों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की शैक्षणिक यात्राएं करती हैं एवं उन प्रतिष्ठनों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व एवं संबंधित संस्थान में कार्यरत संगठनों के ज्ञापनों को संज्ञान में लेती है। हम यहां समिति के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में की गई शैक्षणिक यात्राओं की बात करेंगे।

समिति भारत सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष नीतियों को निर्मित करने हेतु सलाह देती है। भारत में वित्त मंत्रालय की ओर से समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2013 में पहली बार अन्य पिछड़े वर्गों के कार्मिकों लिए दिशा निर्देश जारी किए गए जो पुनः अद्यतन कर वर्ष 2021 में जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों को आपके लिए इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

वर्तमान में संसदीय समिति के माननीय सभापति श्री गणेश सिंह है। माननीय सांसद श्री गणेश सिंह का सभापति के रूप में यह दूसरा कार्यकाल है। बहुत ही प्रभावशाली रूप से श्री गणेश सिंह अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की आवाज को संसद पटल पर रखते रहें हैं। **AIOBC** महासंघ के महासचिव श्री जी0 करूणानिधि ने राज्य सरकार एवं भारत सरकार के लगभग 52 प्रतिष्ठानों में सक्रीय ओबीसी संगठनों की ओर से समिति के समक्ष विभिन्न मांगों को रखा है। समिति इन सभी मांगों को लेकर काफी गंभीर है एवं कई मुद्दों को लेकर समिति ने संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखा है। हमें विश्वास है कि समिति के प्रयासों

सत्यमेव जयते

ओबीसी संसदीय समिति

का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए चेन्नई में शैक्षणिक दौरा

श्री टी0आर0बालू, पूर्व केन्द्रीय पत्तन, पोत्त परिवहन और जलमार्ग, वर्तमान में माननीय सांसद एवं ओबीसी संसदीय समिति के सदस्य का श्री जी0 करूणानिधि द्वारा डाटा पुस्तक देकर सम्मान

का सकारात्मक प्रभाव सरकार के निर्णयों के माध्यम से हमारे समक्ष होगा। यदि हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समिति के अध्ययन दौरे को देखें तो अब तक समिति ने वर्ष 2013 से लेकर 2025 तक कुल 6 बार अध्ययन दौरे किए हैं। प्रत्येक अध्ययन दौरों में समिति शीर्ष प्रबंधन एवं संगठन के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित होते हैं और अपनी बातें रखते हैं। चूंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संगठन एवं प्रबंधन के बीच व्यावसायिक कार्य संबंधी व्यावहारिक पहलू अत्यंत सुलझे हुए हैं इसलिए कभी भी संगठन के द्वारा कोई विरोधात्मक बातें नहीं रखी गई। अपितु **AIOBC** महासंघ के महासचिव श्री जी0 करूणानिधि ने विगत दिनों समिति के समक्ष महासंघ की ओर से कई मुद्दों को रखा है जिसके निपटारे के लिए समिति के माननीय सभापति द्वारा त्वरित एवं उचित कदम उठाया गया है। जैसे ओबीसी रिसर्च स्कॉलर हेतु नेशनल फेलोशिप की राशि का छात्रों को विगत कई महीनों से भुगतान नहीं होने पर समिति ने संज्ञान लेते हुए एचआरडी मंत्रालय को पत्र लिखा एवं संसद में माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। इसी प्रकार ओबीसी छात्रों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में सामान्य के बराबर राशि का होना जबकि ईडब्ल्यूएस के छात्रों का एससीएसटी छात्रों के बराबर शुल्क का होना। महासंघ ने इस संबंध में समिति को पत्र लिखकर निवेदन किया कि यह गलत है जिसपर संज्ञान लेते हुए समिति एवं कुछ अन्य सांसदों ने सरकार को पत्र लिखा है। हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जी0करूणानिधि के प्रयासों से ओबीसी से जुड़ी कई विसंगतियां सही होगीं एवं कल्याण संबंधी अन्य कदम भी उठाए जाएगें।

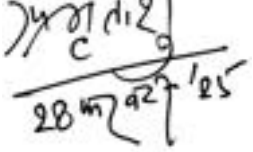

AIOBC
कर्मचारी महासंघ की आम सभा
नई दिल्ली : 6 जनवरी 2025
तेलंगाना भवन

नई दिल्ली/6 दिसम्बर 2024/तेंलगाना भवन : एआईओबीसी कर्मचारी महासंघ की आम सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई। आमसभा में देश के कोने कोने से राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधीन विभिन्न निकायों में कार्यरत लगभग 50 ओबीसी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

आम सभा के प्रथम सत्र में ओबीसी के कल्याण संबंधी विभिन्न विषयों पर महासंघ के महासचिव श्री जी0 करूणानिधि ने विगत वर्षों में महासंघ द्वारा किए गए कार्यों एवं सरकार द्वारा उन बिन्दुओं पर की गई कार्यवाई को सभा के समक्ष रखा। श्री जी0 करूणानिधि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मांगें बहुत ही स्पष्ट हैं और इन सभी मांगों को लेकर फेडरेशन कटिबद्ध हैं। क्रिमीलेयर एक बड़ा मुद्दा है और लम्बे समय से फेडरेशन इसे समाप्त करने की मांग करता रहा है। जाति जनगणना कराने से ही सरकार से पास आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगें। बिना समग्र जानकारी के सरकार कोई भी नीति नहीं बना पाएगी। ऐसी स्थिति में जाति जनगणा कराना सरकार की प्राथमिकताओं में होनी चाहिए। केन्द्र सरकार में पदों की समतुल्यता यानी इक्विवैलेंस ऑफ पोस्ट पर वर्ष 2017 में डी0एफ0एस0 द्वारा निर्देश जारी किए जाने के कारण आज बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के कनिष्ठ अधिकारी भी क्रिमीलेयर के दायरे में आ गए हैं एवं उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। फेडरेशन ने ओबीसी संसदीय समिति एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष इसे पुनर्समीक्षा हेतु रखने और डी0जी0एम0 एवं उनसे उपर के संवर्ग के अधिकारियों को ग्रुप–'ए' / क्लास '1' में रखने की बात कही है जैसा कि बीएसएनएल विभाग में है।

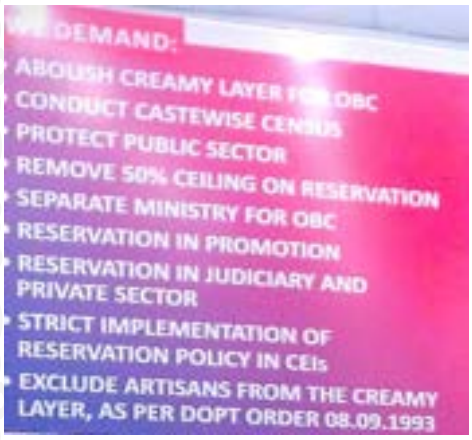

प्रस्तुति : डॉ0 अमृतांशु,
संगठन सचिव : एआईओबीसी कर्मचारी महासंघ

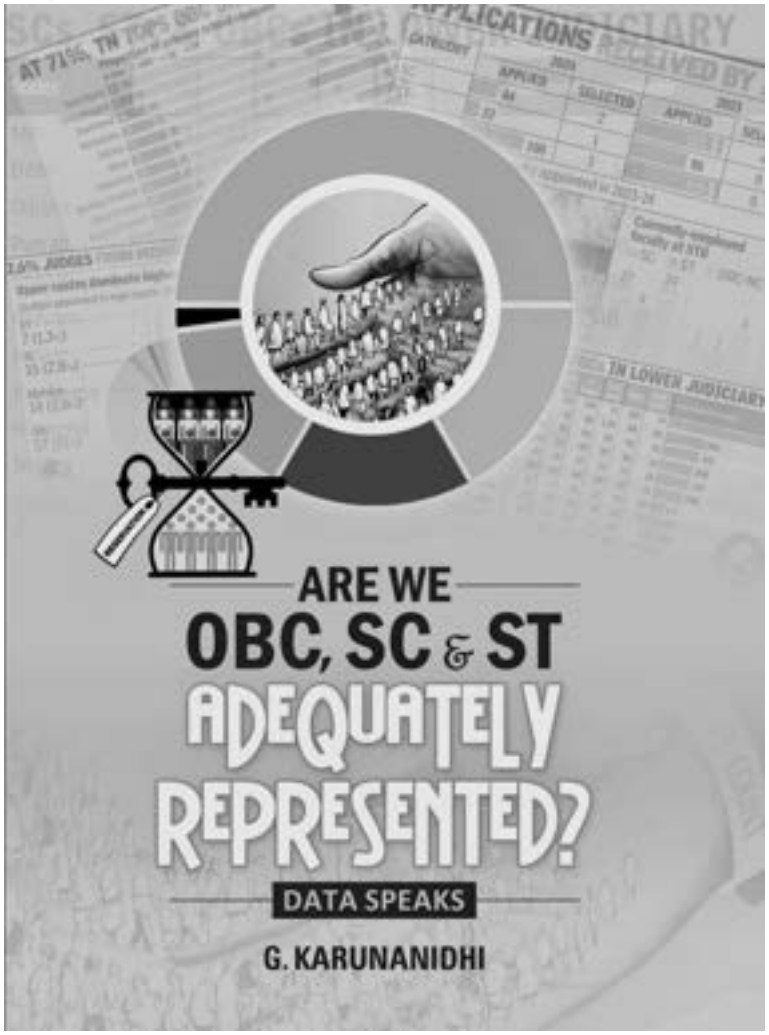

पुस्तक-विमोचन

क्या हम, ओबीसी,एससी,एसटी पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुके है

लेखक एवं संकलनकर्ता

जी० करूणानिधि

प्रकाशक

इम्पॉवर

ट्रस्ट फॉर सोशल जस्टिस

चेन्नई

हिन्दी संस्करण उपलब्ध

प्रस्तुत पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन है। यह पुस्तक माननीय सांसदों, प्रशासनिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है।

पाठक यदि इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस मेल आईडी – empower.socialjustice@gmail.com एवं पुस्तक के लेखक श्री जी0 करूणानिधि के मोबाईल नम्बर : 9381007998 पर सूचित कर पुस्तक मंगा सकते हैं।

–संपादक

यूनियन बैंक Union Bank of India

EMPOWER (TRUST FOR SOCIAL JUSTICE)
QR917695823527-8472@unionbankofindia

Or else NEFT:

Empower Trust for Social justice
SB account No
332602010438472
IFSC: UBIN0533262
Union Bank of India
Chennai Main

Book: Single copy::Rs.100/-,
10 books and above 20% discount

No.20/6/2021-Welfare
Department of Financial Services
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

Jeevan Deep Building Sansad Marg
New Delhi, the 19 July, 2021.

To,

1. The Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), H.O. New Delhi
2. The Chairman, Insurance Regulatory Development Authority (IRDA), H.O. Hyderabad.
3. The Chief General Manager (HRDD), Reserve Bank of India (RBI), Mumbai.
4. The Chairman, LIC of India, Mumbai.
5. The MD & CEOs of all Public Sector Banks.
6. The Chairman, Public Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies.

Subject: Measures for Welfare of persons of SCS/STS/OBCS category and implementation of reservation policy of the Government.

Madam/Sir,

Based on the guidelines issued by Department of Personnel and Training (DoP&T) the nodal ministry on the subject Department has forwarded a number of circulars/ instructions/ guidelines and issued many advisories from time to time, reiterating the obligation of your organization to implement various measures prescribed for Welfare of members of these categories. In these communications, the constitutional and legal obligation about implementation of the reservation policy of the Government in letter and spirit has also been emphasized in unequivocal terms, so as to ensure increasing of the representation of persons of these categories in the Government jobs. In the recent months, this matter has come for review by the Parliamentary Committees and the constitutional authorities many a times. During such reviews, the Department and the financial institutions were frequently reminded about this important obligation of the state towards the members of the SCS/ST/OBCs categories.

2. During the course of these review meetings, a need has been felt that the Banks/financial institutions should be sensitized once again about their responsibility and taking of all necessary measures to implement this well-defined policy of the state. In view of this, various guidelines issued by the Government with regard to reservation and welfare of the persons of SCs/STs/OBCs categories are reiterated as under, for their observance and implementation in the financial institutions in a scrupulous manner:

I. The reservation rosters registers must be prepared by the Banks/financial institutions in accordance with DoP&T guidelines. These rosters are to be countersigned by the Chief Liaison Officer (CLO) for the SCs/STs/OBCs categories appointed by the organization, as a mark of their correct preparedness. These rosters must be uploaded on the websites of the respective organizations for access by the welfare organizations, stakeholders and public at large so as to ascertain correct implementation of the reservation policy during the recruitment / promotion exercises conducted by the organization.

II. Wherever a selection Committee/Board is constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in any level of posts or services, it is mandatory to have one member belonging to SCs/STs, one member belonging to OBCs and one member belonging to minority community in such Committee/Board.

III. With effect from 08.09.1993, there is reservation for OBCs of 27% of the vacancies in civil posts and services under the Government of India to be filled through Direct Recruitment, in addition to a reservation of 15% and 7.5% for SCs & STs respectively, already in force. It is obligatory fo r the organizations to strive and make all necessary efforts to

Contn...

make recruitment in accordance with reservation quota earmarked for each category. For any omission/disregard of these Government instructions during dispensation of this quota, the organization concerned shall be responsible, and directly answerable to these constitutional bodies and Parliamentary Committees, set up for protection of the rights of persons of these categories.

IV. There shall be separate Liaison Officers to look after the welfare and reservation related issues for SCs, STs and OBCs. In accordance with Ministry of Finance letter No. 20/1/2006-SCT(B) dated 02nd March, 2006, the Public Sector Banks/ Financial Institutions may nominate officers of level of General Manager or above as the CLO for SCs, STs and OBCs respectively. These Liaison Officers to be advised to make themselves available to meet the members of reserved category to hear and sort out their grievances in consultation with management. The representatives of the welfare associations of these employees may be allowed to hold two periodical meeting with the management of the organization.

V. The rosters of the organizations should be got inspected and countersigned by the CLOs of Department of Financial Services (DFS) at least once every year. During such inspections, the checklist containing complete picture of various measures adopted by the organizations in this regard is also shown to the CLOs to ascertain orders/instructions. Satisfactory implementation of Government Orders/ Instructions.

VI. It is also noticed that in some organizations, it has been claimed that the roster registers of older period have either been destroyed or are not traceable. Since the roster registers are basic documents to prove manner of implementation of the reservation policy of the Government, it is necessary that such important documents/registers are never lost sight of and these are maintained and stored carefully for future access. It is therefore important that necessary action is taken immediately to re-create the rosters which are not traceable or have been destroyed, on the basis of available records of the relevant periods.

VII. The Welfare associations may be provided office space and other facilities subject to availability of space, at HQ level. At least two office bearers may be posted nearer to the HQ, subject to office exigencies, so as to enable them to take up and sort out their day to day grievances.

VIII. Measures like providing pre-recruitment and pre-promotion training may be taken up by the organizations so as to bring up the employees of these categories at par with other employees. Likewise, adequate number of employees of reserved categories should be nominated for the seminars, symposia, conferences and foreign trainings to enhance their skills.

IX. In various social security schemes of the Government, insurance products, education loans, and credit schemes/ Bank loans, it may please be ensured that the benefit of these schemes reach these categories also in an easy, and simple manner and proper data of beneficiaries of such schemes be maintained.

X. In the Annual Report of the organization, a chapter may be included on the subject of Welfare of SC/ST/OBC categories to describe details of the posts filled up by the candidates of these categories during the year at various levels, their representation in the organization. special training programs/recruitment drives conducted during the year for them, and other measures (like special schemes financial products/credit facilities/ education loans designed and disbursed to the beneficiaries of these categories), adopted by the organization, for welfare, upliftment and empowerment of these persons.

XI. DoP&T has issued certain guidelines about verification of claims of caste by the candidates belonging to SCs, STs and OBCs for purpose of their appointment to posts/services. It may please be ensured that these guidelines are followed by the Bank while conducting the recruitment process.

Contn...

3. The above is not an exhaustive list and hence the institutions shall ensure that all the circulars and instruction/guidelines issued by the DoPT/DFS are complied with seriousness.
4. From the data compiled from various banks/organisations, it has been noted that in some of the organisations, the representation of reserved categories in the jobs is much below the percentages prescribed in the Government policy. Such organisations need to make special efforts like launching of special recruitment drive for filling up of Backlog vacancies reserved for these categories so as to enhance their representation in the services. It is reiterated that making available the quotas earmarked for reserved categories is a legal obligation and failure to comply with these guidelines is considered to be a serious misconduct, attracting disciplinary action. Therefore, the Heads of the Banks/Financial institutions are advised once again to make all out efforts to ensure that the Government guidelines in this regard are followed carefully, during recruitment exercise /promotion processes, the quotas of posts earmarked for each category is made available in a correct and rightful manner, and the same is reflected in the reservation rosters of the organization.

Yours faithfully

(Saroj Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tel.011-23746413
Email-sct@nic.in--

भारत सरकार के समक्ष

त्वरित ध्यानाकर्षण हेतु

DISCRIMINATION AGAINST OBC

TUTION FEES FOR

EWS: ZERO

FOR OBC: Rs.53,000

POST-GRADUATE TUTION FEES IN SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, NEW DELHI
(UNDER THE MINISTRY OF EDUCATION, Govt, of India)

Institution	Tuition Fee for OBC	Tuition Fee for EWS
SCHOOL OF PLANNING & ARCHITECTURE, NEW DELHI	Rs. 53,000	'0'

(Notification dated 13.12.2024)

NON-PAYMENT OF
Fellowship Payments to OBC Research Scholars
since JUNE 2024
by Ministry of Social Justice & Empowerment
"FELLOWSHIP AMOUNT UNDER NFOBC"
(Reply in Lok Sabha to a starred question No.35, dt:04.02.2025 by Union Minister of Social Justice & Empowerment)

APPLICATION FEES: OBC Vs EWS

Institution	Application Fee for OBC	Application fee for EWS
AIIMS	Rs. 3000	Rs.2400
NIT, Manipur	Rs. 2500	Rs.1000
NIT, Silchar	Rs.1000	Rs. 500

(CBE Recruitment 2025 Notification for 4576 Posts and NIT Silchar and Manipur centres)
Without any representation from EWS, all concessions, relaxations, waiving of fees are done for the EWS

IS THE UNION GOVERNMENT MORE CONCERNED WITH
EWS - UPPER CASTE 'POOR'?
THAN THE
THE HISTORICALLY DISCRIMINATED OBCs
(SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES)

Compiled by: G.Karunanidhi, General Secretary (27.02.2025)
AIOBC
ALL INDIA OTHER BACKWARD CLASSES EMPLOYEES' FEDERATION

न्यू इंडिया इन्शयोरेंस ओबीसी एसोसिएशन के कार्यालय का उद्घाटन

मुम्बई /दिनांक 12 फरवरी 2025/ एआईओबीसी महासंघ की संबंधित इकाई एआईजीआईसी ओबीसी कर्मचारी फोरम, न्यू इंडिया एश्योरेंस के मुम्बई में उनके प्रधान कार्यालय द्वारा आवंटित एसोसिएशन कार्यालय का उद्घाटन **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री जी0 करूणानिधि द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्यू इंडिया एश्योरेंस के कार्यपालक श्री के0वी0रमन, महाप्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार खंडेलवाल, डीजीएम – कार्मिक सुश्री जयश्री नायर, महाप्रबंधक एवं संपर्क अधिकारी एवं ओबीसी कर्मचारी संगठन और एस सी एस टी कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

लम्बे संघर्षों के बाद एआईजीआईसी ओबीसी कर्मचारी फोरम को ओबीसी संगठन हेतु कार्यालय का आवंटन संगठन के लिए अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ नई उर्जा के रूप में उपलब्ध हुआ है। पूरी टीम को हार्दिक बधाई।

–शालीन कुमार

जनवरी 2025

संसद सत्र के दौरान

माननीय सांसदों से मिलकर

अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखना

ओबीसी संसदीय समिति के माननीय अध्यक्ष श्री गणेश सिंह जी को पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

माननीय सांसद श्री पी0 विल्सन जी को पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

फोरम ऑफ ओबीसी एमपीज के पूर्व संयोजक सांसद श्री वी0 हनुमंत राव जी को पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

जनवरी 2025 में दिल्ली में ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री गणेश सिंह जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय अध्यक्ष श्री हंसराज अहिर जी, एवं अन्य माननीय सांसदों से मिलकर उन्हें ओबीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन दिया और आग्रह किया कि इन विषयों पर आपकी त्वरित कार्यवाई प्रार्थनीय है। क्रिमीलेयर एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा जाति जनगणना कराने से ही सरकार से पास आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगें। अतएव जाति जनगणना कराना अतिआवश्यक है।

इक्विवैलेंस ऑफ पोस्ट पर वर्ष 2017 में डी0एफ0एस0 द्वारा निर्देश जारी किए जाने के कारण आज बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के कनिष्ठ अधिकारी भी क्रिमीलेयर के दायरे में आ गए हैं एवं उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।

—प्रस्तुति :
शालीन कुमार

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय अध्यक्ष श्री हंसराज अहिर जी को पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि

माननीय सांसद श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी को सम्मान करते एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं सं0 सचिव डॉ0 अमृतांशु

माननीय सांसद श्री कृष्णईया जी को आंकड़ों की किताब एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

जनवरी 2025

संसद सत्र के दौरान

माननीय सांसदों से मिलकर

अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखना

माननीय सांसद श्री शंमुगम जी को आंकड़ों की किताब एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

माननीय सांसद श्री मनीकम टेगोर जी को आंकड़ों की किताब एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

हम आपकों सूचित करते चलें कि जनवरी 2025 में दिल्ली की यात्रा के दौरान एआईओबीसी कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री जी0 करूणानिधि ने AIIMS, NIT आदि कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के एडमिशन फी में ओबीसी के छात्रों के लिए सामान्य के बराबर फी शुल्क रखे जाने एवं ई0डब्लयू0एस0 श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए फी एससी एसटी के बराबर रखे जाने के मसले को ओबीसी संसदीय समिति एवं अन्य माननीय सांसदों को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया। परिणामतः यह मसला माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संज्ञान में लाया गया। अति आवश्यक है। इसी प्रकार ओबीसी के मेधावी रिसर्च स्कॉलर के लिए स्वीकृत नेशलन फेलोशिप को लगभग जून 2024 से नहीं दिया जाने के मसले को भी समिति के माध्यम से उठाया गया, परिणाम स्वरूप संबंधित मंत्रालय को विषय को संज्ञान में लेना पड़ा।

—प्रस्तुति :
शालीन कुमार

माननीय सांसद डॉ0 शिवदासन जी को आंकड़ों की किताब एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

माननीय सांसद श्री जॉन ब्रुटस जी को आंकड़ों की किताब एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

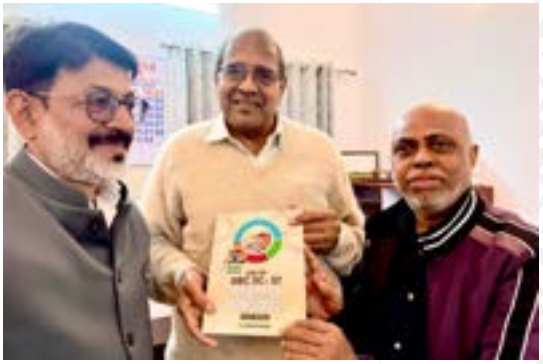

माननीय सांसद श्री सुब्बा रायन जी को आंकड़ों की किताब एवं पत्र सौंपतें **AIOBC** कर्मचारी महासंघ के महासचिव जी0 करूणानिधि एवं संगठन सचिव डॉ0 अमृतांशु

माननीया राष्ट्रपति को पत्र

Website: www.aiobcfederation.org
Email: aiobcfederation@gmail.com
Mobile: +91 938 100 7998

AIOBC

AIOBC
ALL INDIA OTHER BACKWARD CLASSES EMPLOYEES' FEDERATION

AIOBC

(Formerly All India Federation of Other Backward Classes Employees' Welfare Associations)
Correspondence Address: 139, Broadway, Chennai 600108 (Tamil Nadu)

February 19, 2025

Our memorandum submitted to Hon'ble President of India sent to the Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for necessary action.

On behalf of our Federation, Dharna and Seminar programs was conducted on 5th December 2024, On that occasion, a memorandum addressed to the Hon'ble President of India was **submitted to the Officials of the President Secretariat, on behalf of our Federation, by our office-bearers U.Chinnaiah, Vice-President and Dr.Amritanshu, Org. Secretary.**

The memorandum includes the following OBC matters:

1. **Caste-wise data in Census:**
2. **Remove creamy layer**
3. **50% ceiling to be removed to provide 52% reservation for OBCs**
4. **Equivalence of Posts: Govt vis-à-vis PSUs.**
5. **Reservation in promotion for other Backward Classes to reach adequate representation in the services of the State.**
6. **Protect Public Sector Enterprises**
7. **Separate Ministry for welfare of OBC**
8. **Adequate budget allocation for OBC welfare and creation of Special Component Plan for OBCs in the Union Budget**
9. **Strict Implementation of Reservation Policy in Central Educational Institutions including IITs, IIMs, AIIMS etc.**
10. **Reservation in Judiciary**
11. **Reservation in private sector**

We wish to inform that the President's Secretariat has intimated us that the said memorandum has been sent to the Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India with a direction that action taken on the petition be communicated to the Federation **(vide its communication dated 24.01.2025 under copy to our Federation).**

We hope the Ministry of SJ&E will react to our representations early and favourably.

G.Karunanidhi
General Secretary

राष्ट्रपति सचिवालय

से भारत सरकार को पत्र

AIOBC फेडरेशन को कॉपी द्वारा सूचित

1/28/25, 5:38 PM

Petition

President's Secretariat (PUBLIC-I SECTION)

Rashtrapati Bhavan

New Delhi - 110004

Ministry of Social Justice and Empowerment

Room No. 611,A Wing, Shastri Bhawan,New Delhi

Subject: REQUEST FOR ATTENTION ON HIS/HER PETITION

Enclosed please find for appropriate attention a petition dated 05/12/2024 addressed to the President of India on the above subject matter, which is self explanatory.

Action taken on the petition may please be communicated to the petitioner directly.

Copy to:

Shri G. KARUNANIDHY

135, BROADWAY,

CHENNAI,

TAMIL NADU

INDIA

You are further requested to liaise with the aforementioned addressee directly for further information in the matter.

(GAUTAM KUMAR)

Under Secretary

ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

To

Shri G. KARUNANIDHY

135, BROADWAY, CHENNAI,

TAMIL NADU

INDIA

110001 07.02.2025

15CF 00151454

₹5.00

P880303

दिनांक 5 दिसम्बर 2024 को **AIOBC** फेडरेशन की ओर से महासचिव **श्री जी0 करूणानिधि** द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति सचिवालय में माननीया राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों को सौंपते हुए महासंघ के उपाध्यक्ष **श्री यू0 चिन्नईया** एवं संगठन सचिव **डॉ0 अमृतांशु**

भारत सरकार द्वारा जारी
बैंकों हेतु स्थानान्तरण नीति पर **श्री जी० करूणानिधि** का
IBA और बैंकों के प्रबंध निदेशक को पत्र

Letter on TRANSFER POLICY dated 13.1.2025 addressed to Chairperson, IBA under copy to Chairpersons of PSBs, Secretary, DFS, Chairperson of Parliamentary Committee for OBC

Review of Transfer Policy for Public Sector Banks - DFS advisory to be implemented in all Banks from FY 2025-26

We have for reference the Guidelines issued by Department of Financial Services (Ministry of Finance) dated 26.11.2024 on New Transfer Policy for Public Sector Bank Employees.

Now today i.e. on 13 January 2025, again the Finance Ministry has asked Public Sector Banks to implement new transfer policy immediately. The Finance Ministry has said that FY 2025-26 transfer exercises will be held as per the new transfer policy.

In this regard, we have to state that due to this abrupt transfer of officers on the guise of 'long stay', our OBC Officers were mostly affected. As first-generation officers belonging to OBCs, many of them have encountered significant difficulties and hardships, especially when it comes to leaving their families behind and adapting to work in different states that feature diverse cultures and languages. This situation has not only impacted their professional lives but also their personal stability and emotional well-being.

Few of our Hon'ble Members of Parliament have raised these matters with the bank managements and Hon'ble Finance Minister.

As such, we, an association striving for protecting the interests of OBCs, were compelled to take up this transfer policy which is against our interests with the Government.

By our letter of 25th April 2023, we insisted the following:

"Though as a Welfare Association, we have not been invited for discussion in transfer policy matters affecting the OBC members, we have been requesting the management that ***up to Scale III, officers need not be transferred out of the Zone. It is very much enough if officers from Scale IV onwards are moved out to different areas / Zones for better executive / administrative exposures and skills.***

1. *Where non-availability of vacancies exists, officers with longer stay in a particular* ***Region*** *may be transferred within the Zone.*
2. *In doing so, the* ***Lady Officers be exempted*** *considering their family situation and as per* ***Finance Ministry (DFS) guideline F.No.4/9/1/2014/IR dated 8.8.2014****, copy of which is enclosed.*
3. *Requests on Medical grounds may be given consideration and exemption.*
4. ***Office-bearers of our Welfare Association, both at the All India and State level be exempted from this lateral policy, if such exemptions are extended to Office bearers of Officers/Welfare Associations"***

The representation of the Hon'ble MPs as well as ours were well taken by the Hon'ble Finance Minister and we thank and appreciate Madam for the responsiveness to these pressing concerns.

Accordingly, The Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance has directed State Bank of India and other public sector banks (PSBs) to revamp their transfer policies for the officer employees following a surge in complaints regarding their implementation. The guidelines states:

1. Rotational transfers should be based on seniority.
2. Online platform will be developed for the transfer process, allowing employees to choose location preferences.
3. Officers up to Scale-III should be accommodated in their respective linguistic regions.
4. Additional grounds for transfer should be included – such as marriage, spouse, medical needs, maternity, child care, and distant postings.
5. Efforts should be made to post employees in the same or nearby regions if their spouse works in Central or State Governments.
6. Women employees should be transferred to nearby locations.
7. Employees can appeal against unfair transfer. A grievance committee should be formed and appeals should be resolved within 15 days. Appeals should be dealt with kindly and committee should try to resolve the issue and proper reason should be given in writing.

Banks have been asked to take Board approval for the advised changes to the 'Transfer Policy' and undertake implementation and compliance from FY 2025-26.

Now that the DFS has issued the advisory, we would request you to kindly advise all the public sector banks including SBI to implement the transfer policy in line with the guidelines of the DFS dated 26.11.2024 from this Financial Year (2025-26).

We look forward to your early action.

- G.Karunanidhi, General Secretary, AIOBC Employees Federation

अखिल भारतीय यूनियन बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ

की प्रबंधन के साथ दिनांक 24 फरवरी 2025 को बैंक के मुम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय में छमाही बैठक हुई। बैठक बैंक के उच्च एवं शीर्ष कार्यपालकों के साथ संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच विभिन्न कल्याणकारी विषयों पर आधारित होती है।

भारत सरकार द्वारा जारी
बैंकों हेतु स्थानान्तरण नीति

eF. No. 4/1/2/2024-IR (आई. आर.)
भारत सरकार/Government of India
वित्त मंत्रालय/Ministry of Finance
वित्तीय सेवाएँ विभाग/Department of Financial Services

3rd floor, Jeevan deep Building
Sansad Marg, New Delhi – 110 001
26th November, 2024

To:

Chairman, State Bank of India;
Managing Director & CEOs, Nationalised Banks

Subject: Review of Transfer Policy in Public Sector Banks – reg.

Madam / Sir,

This Department has accorded managerial autonomy to the Public Sector Banks (PSBs) in matters related to Human Resources (HR) and has been communicating broad guidelines, from time to time, regarding HR reforms including relevant instructions of the Department of Personnel & Training for incorporation in their respective 'Transfer Policy'.

2. This Department has observed an increasing trend in the complaints / grievances received with regard to the 'Transfer Policy' and its implementation by the PSBs. Such complaints / grievances are received through various forums and from various dignitaries.

3. In view of the above, the 'Transfer Policy' of the banks have been reviewed and with an aim to promote greater transparency, and to ensure formulation of a uniform and non-discretionary 'Transfer Policy', PSBs are advised as below:

a. Various administrative layers in the Bank such as Region / Zone / Circle / FGMO etc. be clearly and uniformly defined. Similarly, minimum and maximum tenure at each layer be also clearly defined.

b. 'Transfer timelines' be clearly defined and strictly adhered to. Transfer exercises may be completed before June, every year. Mid-year transfers may be avoided as far as possible except in case of promotions and administrative exigencies.

c. Transfer exercise be made transparent with annual publication of seniority list and the existing / expected vacancies at different locations / scales. Rotational transfers should be on seniority basis and exceptions, if any, should be properly recorded / documented.

Page 1 of 2

d. Banks to automate the transfer process and to develop an online platform for the same with the facilities of giving location preference options to its employees in case of transfers. The online portal may also include the Bank's transfer policy, guidelines and related circulars, scale wise seniority list, details of vacancies scale wise/location wise, and other relevant details in order to bring efficiency and transparency in transfer process.

e. Banks to accommodate officers up to Scale-III in the respective linguistic region in order to ensure seamless customer service to the extent possible, considering various factors including availability of vacancies, administrative exigencies etc.

f. Banks to designate certain regions as 'Difficult areas'. The employees posted there be given preference for transfer after completion of their tenure.

g. In addition to the available grounds of transfer, the grounds of marriage / spouse / medical / maternity / child care / far away postings also be suitably incorporated.

h. In case of spouse working in Central / State Governments, an endeavour to post them in the same place / region or nearby place / region be made.

i. Women employees be transferred as far as possible to nearby places / stations / region. In case of posting to a far-away / remote locations, their safety be given due importance and availability of basic amenities be ensured.

j. Grievances received from employees citing violation of transfer policies be dealt in a considerate manner and suitably responded after detailed deliberations and by duly recording the reasons thereof.

k. With respect to appeals received on transfers from the employees, a committee be set up to look into the issue and dispose the appeals within 15 days.

l. With regard to 'Transfer protection' to office bearers of Associations / Unions, clear definition of position, tenure and applicability be incorporated and strictly adhered. Transfer protection may not be made available to an office bearer on promotion.

4. All PSBs are requested to incorporate the above advises suitably in their respective 'Transfer Policy' with the approval of their Boards and take immediate action for its implementation and compliance from FY 2025-26. PSBs are also advised to send a copy of the policy, so modified, to this Department, at the earliest.

Yours faithfully,

(विजय शंकर तिवारी/Vijay Shankar Tiwari)
अवर सचिव, भारत सरकार/
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23362349; Email: ir@nic.in

प्रोफेसर एस०एस०कुशवाहा
जन्मदिन की हार्दिक बधाई

1 जनवरी 2025 को डॉ0 अमृतांशु एवं श्री आलोक कुमार ने रांची विश्वविद्यालय एवं महात्मा काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉ0 सुरेन्द्र सिंह कुशवाहा को उनके आवास पर जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। संगठन एवं ट्रस्ट उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता है।

चेन्नई स्थित यूनियन बैंक ओबीसी संगठन कार्यालय में उपस्थिति

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री हंसराज अहिर जी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए श्री जी0 करूणानिधि एवं डॉ0 अमृतांशु

दिनांक 5 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति सचिवालय में माननीया राष्ट्रपति को ज्ञापन/प्रार्थना पत्र सौंपते हुए श्री यू0 चिन्नईया एवं डॉ0 अमृतांशु

टोल फ्री नं : 1800 208 2244/ 1800 425 3555 / 1800 425 1515
@unionbankofindia @UnionBankTweets @unionbankofindia UnionBankInsta UnionBankofIndiaUtube